प्रक्रिया

- यूनिफॉर्म की आपूर्ति राज्य के समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर की जा रही है।
- ब्लॉक मुख्यालयों से अधीनस्थ पीईईओ के माध्यम से अधीनस्थ समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की जा रही है।

अब तक

कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित

पात्रता

राज्य सरकार के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 तक (निदेशालय, प्रा. शि., मा.शि., संस्कृत शिक्षा, जनजाति कल्याण विभाग एवं समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विद्यालय) के 67,58,177 विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई गई है।

अधिक जानकारी के लिए 181 पर कॉल करें या
https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर विजिट करें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#मॉडल_स्टेट_राजस्थान

4 वर्ष
जनसेवा, सबका सम्मान
आगे बढ़ता राजस्थान
सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म

मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना

स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम

परिचय

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2021-22 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की घोषणा की गई।

निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा दिनांक 29.11.2022 को किया गया। समग्र शिक्षा परियोजना अन्तर्गत 48,39,758 विद्यार्थियों (सभी लड़कियां, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, बीपीएल वर्ग के लड़के) को निःशुल्क यूनिफॉर्म के दो सैट हेतु राशि 290.39 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं इसमें से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का अंश क्रमशः 174.23 करोड़ रूपये एवं 116.16 करोड़ रूपये है। शेष रहे 19,18,419 विद्यार्थियों (सामान्य, ओबीसी, एसबीसी वर्ग के लड़के) हेतु राज्य सरकार राशि रूपये 115.10 करोड़ राज्य मद से वहन कर रही है।

यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु राशि 200 रुपए प्रति विद्यार्थी को डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित किये जाने हेतु वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कुल राशि 94.61 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना के क्रियान्वयन में राशि 500.10 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इस व्यय में "राजस्थान सरकार द्वारा वहनीय 325.87 करोड़ रुपए" है।

निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण से विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन (वृद्धि) होगा एवं ड्रॉपआउट घटेगा। इस योजना से विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता एवं एकरूपता आएगी तथा अनुशासनात्मक परिवेश का विकास होगा।